Plan for the development of that territory;

(b) if so, when was the plan submitted; and

(c) the action taken thereon?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Government of Goa, Daman and Diu asked for technical assistance in the preparation of a Regional Plan for the development of Goa District.

(b) and (c). The plan was prepared by the Town and Country Planning Organisation of Government of India and sent to the Government of Goa, Daman and Diu in April, 1977. The Plan is being processed by the Union Territory Government for publication under its Town and Country Planning Act.

कैम्पों में रह रहे शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता

5570. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भिन्न-भिन्न शरणार्थी शिविरों में ऐसे कितने शरणार्थी हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की गयी है और वे कितने वर्षों से शिविरों में रह रहे हैं;

(ख) उन पर प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाता है और इस मद पर अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है ;

(ग) इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में सरकार को क्या आपत्ति है ; और

(घ) उन्हें शीघ्र भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) शिविरों में रह रहे शरणार्थी परिवारों की कुल संख्या 14,671 है, इनमें 1970 में से भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के 4,485 परिवार है और भारत-पाक संघर्ष 1971 के दौरान भारत में आए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के 10,186 परिवार है ।

(ख) इन पर प्रतिवर्ष लगभग 376.00 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं जिसमें से प्रवासियों पर 126.00 लाख रुपये और पाकिस्तान राष्ट्रिकों पर 250.00 लाख रुपये हैं । 1976–77 तक इस मद पर किया गया कुल खर्च 15,329.82 लाख रुपये है जिसका विभाजन इस प्रकार है—प्रवासियों के लिए 14,284.00 लाख रुपये और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए 1,045.82 लाख रुपये ।

(ग) जहां तक प्रवासियों का सम्बन्ध है, उन्हें नागरिकता प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में दी गई शर्तों के अनुसार, वे पंजीकृत किए जाने के पात्र हैं ।

जहां तक पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का सम्बन्ध है, सरकार ने इस प्रश्न पर इस पहलू से अभी तक विचार नहीं किया है ।

(घ) गृह मंत्रालय तथा पुनर्वास विभाग द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर हिदायतें जारी की गई हैं कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में की गई व्यवस्था के अनुसार पात्र प्रवासियों को शीघ्र नागरिकता प्रदान की जाए ।

Intensive Rural Development Scheme for Cannanore District of Kerala

5571. SHRI RAMACHANDRAN KADANNAPPALLI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Cannanore District of Kerala is one of the districts selected

under the intensive rural development scheme; and

(b) if so, salient features thereof and progress, if any, made so far?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Cannanore District of Kerala is one of the Districts selected under the 'Integrated Rural Development programme', and not Intensive Rural Development Programme as there is no programme by this name.

(b) The programme aims at generation of employment opportunities for 'rural poor' and 'disadvantaged groups' through optimum use of local resources setting up agro-based, forest-based and village and small industries in rural areas, intensification of agriculture, animal husbandry and dairy, poultry and piggery, taking up meaningful programme for small and marginal farmers, agricultural labourers, share croppers and tenants and rural artisans and encouraging self employment schemes.

The programme consists of two phases viz., (i) preparation of resources inventories and action plans for selected districts and (ii) implementation of the programme. Work on the preparation of Integrated resources inventory for Cannanore District has been entrusted by the Indian Council of Agricultural Research to the Water Technology Centre, I.A.R.I. who are doing it with the cooperation of the State Government. This exercise is likely to be completed soon. The analysis of resources, inventory would throw up a series of action plans which will be finalised in consultation with the State Government.

Development of Hot Pressed Garnets

5572. DR. HENRY AUSTIN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether for the first time the Indian Institute of Technology, Bombay has successfully developed hot pressed garnets;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) whether the technique developed is expected to meet the country's requirement?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) These garnets are used in high power ferrite devices like isolators and circulators which are, in turn used in satellite, radar and other microwave communications. These garnets are comparable favourably with similar material available at present from advanced countries.

(c) According to the IIT, Bombay, if production agencies adopt the technique which has been developed, it should not be difficult to meet the current requirements of the country.

राजस्थान के झुंझुनू जिले की रिजानी पहाड़ी में छिपी धन सम्पत्ति

5573. **श्री लालजी भाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के झुंझुनू जिले की रिजानी पहाड़ी में अथाह धन-सम्पत्ति छिपी पड़ी है ;

(ख) क्या पहाड़ी की एक ऊंची चट्टान के भीतर एक शिलालेख उत्कीर्ण है जिस पर लिखी भाषा पढ़ी नहीं जाती ;

(ग) क्या इस पहाड़ी पर कुछ व्यक्तियों को प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनसे पहाड़ी में छिपे धन की पुष्टि होती है ; और